Title: Need to take suitable measures in consultation with Government of Nepal to check recurrent floods in Bihar.

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, हर वर्ा की भांति इस वर्ा भी बिहार के द्वार पर बाढ़ ने दस्तक दे दी है। गत वर्ाों में बिहार ने इस कारण 1,48,863 करोड़ रुपये की हानि हुई है और भविय में भी जब तक समस्या का समाधान नहीं होता, यह हानि लगातार होती रहेगी। सरकार ने गत वर्ाों में अतिरिक्त जल को नियंत्रित करने के लिए राट्रीय जल बोर्ड के माध्यम से हिमालय घटक की नदियों से संबंधित 14 परियोजनाएं तैयार की थीं। इनमें 6 परियोजनाएं सीधे बिहार को लाभान्वित कर सकती थीं, परन्तु योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हुआ। अन्य 2 परियोजनाएं बिहार की बाढ़ की रोकथाम के लिए बनाई गईं। निर्माण लागत 10.5 करोड़ रुपये तय हुई। 2001-2002 में 3.84 करोड़ रुपये आबंटित किये गये परन्तु इसके आगे न तो राशि आबंटित हुई और न ही निर्माण कार्य आगे बढ़ा।

मेरा आपसे आग्रह है कि बिहार की बाढ़ की समस्या राज्य सरकार के वश की बात नहीं है। यह अंतर्राट्रीय मामले से जुड़ी है। अतः केन्दीय सरकार को सक्रिय होना होगा। नेपाल से वार्ता कर अविलम्ब बिहार की बाढ़ समस्या का समाधान करना होगा।